भारतीय किसानों के लिए भारत–अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के खतरे

24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रम्प भारत की दो दिवसीय यात्रा पर थे। यह माना जा रहा था कि इस दौरान वे प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के साथ एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद यह बयान आया कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता का ''पहला चरण'' पूरा किया जाएगा – संभवतः इस साल के खत्म होने से पहले।[1] बाद में एक बड़ा और व्यापक व्यापार समझौता किया जाएगा।

इस प्रस्तावित समझौते की घोषणा भारत के करोड़ों छोटे खाद्य उत्पादकों और असंगठित व्यापारियों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि इसका सीधा असर उनके ऊपर पड़ने वाला था। इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई भी चर्चा या परामर्श नहीं हुई है, न ही इसे सार्वजनिक किया गया है। भारत की संसद में भी इसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय कृषि क्षेत्र ही इसका लक्ष्य है। दोनों ही देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनर हैं। सामान्य व्यापार के मामले में, भारत अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा पार्टनर है, और अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है। भारत और अमेरिका के बीच माल (goods) का द्विपक्षिय व्यापार करीब 8,790 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 6.6 लाख करोड़ रुपये) प्रतिवर्ष का है, जबकि सेवा (service) क्षेत्र में यह द्विपक्षीय व्यापार करीब 5,480 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 4.1 लाख करोड़ रुपये) का है।

फिर भी इन दोनों देशों के व्यापार संबंधों में पिछले कुछ समय से कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार, डेयरी जैसे मुद्दों के ऊपर गहरी असहमतियों के कारण खटास आई है। हाल ही में, प्रशुल्क (tariff) एवं बाजार में प्रवेश (market access) को लेकर विवाद और भी गहराया है। इस विवाद का एक बड़ा हिस्सा विश्व व्यापार संगठन (WTO) में पहले से ही चल रहा है। लेकिन अमेरिकी डेयरी कंपनियां और कॉरपोरेट घराने लगातार भारत के खिलाफ वाशिंगटन के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। इन्होंने 'अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय' (Office of US Trade Representative) में भारत के खिलाफ ये याचिका भी दर्ज की है कि भारत ''अपने बाजार में बराबर और यथोचित प्रवेश'' देने में विफल रहा है।[2] अब ट्रम्प प्रशासन सीधे मोदी के साथ बातचीत करके एक समझौता करना चाहता है। पिछले 3 वर्षों में दक्षिण कोरिया, चीन, कनाडा और मैक्सिको के साथ ट्रम्प ने जिस प्रकार के व्यापार समझौते किए हैं उनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरीका–भारत व्यापार समझौता भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बुरा होने वाला है।

---

[1] "Trump, Modi hope talks lead to phase one of U.S.-India trade deal: White House", Reuters, 26 February 2020, https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-india/trump-modi-hope-talks-lead-to-phase-one-of-u-s-india-trade-deal-white-house-idUSKCN20K0LN

[2] Press Release, "USTR Announces New GSP Eligibility Reviews of India, Indonesia, and Kazakhstan", Office of the United States Trade Representative, 12 April 2018, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/april/ustr-announces-new-gsp-eligibility

ट्रम्प द्वारा किए गए अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते

अपने चुनावी अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा किए गए व्यापार समझौतों की काफी आलोचना की थी। ट्रम्प का यह कहना था कि अभी तक के सभी व्यापार समझौते अमेरिकी कामगारों के लिए सही नहीं है। शायद यह चुनाव जीतने की एक चाल थी। राष्ट्रपति बनने के बाद, ट्रम्प ने कई समझौतों पर दोबारा बातचीत शुरू कर दी, एक को वापस ले लिया (ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप), और विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकलने की धमकी देने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने जापान के साथ एक आंशिक समझौता कर लिया, अमेरिकी–दक्षिण कोरिया मुक्त व्यापार समझौता को बदल दिया, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत शुरू कर दी (जिसे अब अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता या 'USMCA' कहा जाता है), और चीन, भारत, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम (ब्रेक्सिट के बाद) के साथ नए मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत शुरू कर दी। ट्रम्प तो सब–सहारा अफ्रीकी देश, केन्या के साथ भी पहला व्यापक मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत करने पर उतारू हैं। ये सारी प्रक्रियाएं डोनाल्ड ट्रम्प के – ''अमेरिका सबसे आगे'' – नारे रूपी शब्दाडंबर को आगे बढ़ाने के लिए है। USMCA और केन्या समझौते के अलावा, अन्य सभी मुक्त व्यापार समझौतों का दायरा आंशिक है, जिसमें कुछ ही क्षेत्र या नियम शामिल हैं।

ट्रम्प के भारत दौरे के बाद, अब भारत–अमेरिका के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता होना करीब–करीब तय हो गया है, बस कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। तब तक दोनों ही देश एक 'मिनी' (छोटा) समझौता या ''पहले चरण'' के रूप में कोई समझौता हासिल करने के कोशिश करेंगे – ठीक वैसा ही जैसा अमेरिका ने चीन के साथ किया है।[3] 'मिनी' या छोटे व्यापार समझौते करना ट्रम्प की प्रवृत्ति है। ये जल्दी तय हो जाते हैं और इनके लिए अमेरिकी कांग्रेस की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जरूर है कि ट्रम्प के लिए इन 'मिनी' समझौतों पर हस्ताक्षर करना आसान साबित हो रहा है, पर कई अमेरिकी सांसद इस बात से नाखुश, क्योंकि इन समझौतों में कई महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं। साथ ही ये विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के भी खिलाफ हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुसार सदस्य देशों को द्विपक्षीय या क्षेत्रीय व्यापार समझौते करना चाहिए जिसमें ''मूलतः सभी व्यापार'' शामिल हों, और जिससे कोई भी देश किसी दूसरे देश के खिलाफ भेदभाव न कर सके।[4]

किसान क्या उम्मीद कर सकते हैं

अमेरिकी कृषि के ऊपर बड़े कृषि–व्यवसाय कार्पोरेट घरानों का नियंत्रण है और यह पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर है।[5] हालांकि, लगातार कोशिश करने के बावजूद भी अमेरिका अभी तक अपने कृषि उत्पादों के लिए भारत के बाजार को खुलवा पाने में कामयाब नहीं हो पाया है।

2010 में, उस वक्त के अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (US Trade Representative), रॉन किर्क ने अमेरिकी मंत्रीसभा (सीनेट) में एक सवाल के जवाब देते हुए कहा था, ''हम असामान्य रूप से निराश हैं। आमतौर पर हम सार्वजनिक

---

[3] Banikinkar Pattanayak, "Indo-American trade: FTA talks may start after US elections", Financial Express, 16 March 2020, https://www.financialexpress.com/economy/indo-american-trade-fta-talks-may-start-after-us-elections/1898686/

[4] New York Times, "Trump's Art of the Minideal: Why India-US Trade Truce After 'Howdy, Modi' May Steer Clear of Thorny Issues", News18 India, Washington, 22 September 2019, https://www.news18.com/news/india/trumps-art-of-the-minideal-why-india-us-trade-truce-after-howdy-modi-may-steer-clear-of-thorny-matters-2318515.html

[5] Keith Good, "US Agricultural Trade Developments: China, the European Union, and India", Farm Policy News, 26 January 2020, https://farmpolicynews.illinois.edu/2020/01/u-s-agricultural-trade-developments-china-the-european-union-and-india/

रूप से कोई टिप्पणी नहीं करते हैं कि हम कोई वैधानिक एक्शन लेंगे या नहीं, लेकिन आज मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सभी उपलब्ध वैकल्पिक और प्रवर्तन उपायों (enforcement tools) के इस्तेमाल के बारे में सोच रहे हैं, जिससे भारत के बाजार को कुछ कृषि मुद्दों के लिए खुलवाया जा सके।''[6] करीब 10 साल बाद भी ज्यादा कुछ नहीं बदला है। जून 2019 में भारत ने अमेरिका के 28 उत्पादों के ऊपर 'प्रतिशोध टैरिफ' (retaliatory tariffs) लगा दिया था, जिसमें कृषि संबंधी वस्तुएं भी शामिल हैं।[7]

सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प ने ये घोषणा की थी कि वे भारत में अमेरिकी निर्यात के विस्तार के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद, भारत ने 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी' (RCEP) की वार्ताओं से अपने आप को बाहर निकाल लिया था। बाद में भारतीय वाणिज्य मंत्री ने घोषणा की के भारत अब अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ नए व्यापार समझौतों के बारे में सोच रहा है।[8] उन्होंने यह भी कहा कि भारत जल्दीबाजी में किसी भी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, और किसानों, डेयरी क्षेत्र, छोटे उद्योग और घरेलू निर्माण के हितों को हमेशा ध्यान में रखेगा।[9] दरअसल, यह भारतीय किसानों और ग्रामीण समुदायों का, खासतौर पर डेयरी किसानों का ही दबाव था जिसके कारण भारत को आर.सी.ई.पी वार्ता से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यह सबको समझ में आ गया था कि ये वार्ता उनके लिए किसी आपदा से कम नहीं।[10]

पर ये अमेरिका–भारत मुक्त व्यापार समझौता तो आर.सी.ई.पी. से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। भारत के करोड़ों किसानों (जिनकी औसतन जोत 1 हेक्टेयर या उससे कम है) को अमेरिका के किसानों (जिनकी औसतन जोत 176 हेक्टेयर या उससे अधीक है) के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा। अमेरिका में करीब 21 लाख खेत हैं जिसमें वहां की 2 प्रतिशत से भी कम आबादी को रोजगार मिलता है। वहां की औसतन वार्षिक कृषि आय 18,637 अमेरिकी डॉलर (करीब 14 लाख रुपये) प्रति परिवार है – ये केवल कृषि से होने वाली आय है।[11] दूसरी तरफ, भारत की 130 करोड़ आबादी में से आधी से ज्यादा आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यहां आय के सभी स्रोतों को मिलाने के बाद भी औसतन वार्षिक आय प्रति कृषि परिवार 1,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 75,000 रुपये) से भी कम है।[12]

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का पहला चरण कृषि के ऊपर ही केंद्रित होगा। इसलिए इस रिर्पोट के माध्यम से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारत–अमेरिका व्यापार समझौता का विभिन्न कृषि क्षेत्रों या उत्पादों के ऊपर क्या असर पड़ेगा।

---

[6] PTI, "US considering legal tools to force India to open up farm market", The Economic Times, Washington, 6 August 2010, https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/us-considering-legal-tools-to-force-india-to-open-up-farm-market/articleshow/6264879.cms

[7] Gireesh Chandra Prasad, "India's retaliatory tariffs on 28 US products comes into effect", LiveMint, New Delhi, 16 June 2019, https://www.livemint.com/politics/policy/india-imposes-tariffs-on-28-us-goods-as-global-trade-war-heats-up-1560616982719.html and Notification No.17/2019-Customs, Ministry of Finance (Department of Revenue), Government of India, New Delhi, 15 June 2019, https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2019/cs-tarr2019/cs17-2019.pdf

[8] PIB, "India exploring trade agreements with USA & EU; FTAs with Japan, Korea & ASEAN being reviewed; No trade agreements in a hurry says Piyush Goyal", Ministry of Commerce and Industry, 5 November 2019, Delhi, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1590538

[9] PIB, "India exploring trade agreements with USA & EU; FTAs with Japan, Korea & ASEAN being reviewed; No trade agreements in a hurry says Piyush Goyal", Ministry of Commerce and Industry, 5 November 2019, Delhi, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1590538

[10] GRAIN & ICCFM, "Resisting RCEP from the ground up: Indian movements show the way", 29 January 2020, https://grain.org/e/6391

[11] "US farm income outlook for 2018", Table A-2, Congressional Research Service, 11 December 2018, https://fas.org/sgp/crs/misc/R45117.pdf

[12] ANI, "Average monthly income per agricultural household is less than Rs 6,500, says Agri Min", Business Standard, 26 July 2019, https://www.business-standard.com/article/news-ani/average-monthly-income-per-agricultural-household-is-less-than-rs-6-500-says-agri-min-119072600743_1.html

डेयरी क्षेत्र

अमेरिका ने भारत के डेयरी बाजार में प्रवेश करने के लिए बड़े तिगड़म लगाए हैं पर हमेशा उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। 2003 से भारत ने डेयरी आयात के ऊपर 'सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी' (sanitary and phytosanitary) मानक लगा रखा था, जिसके कारण हमारे यहां अमेरिकी माल का प्रवेश पूरी तरह से अवरुद्ध था। पर दिसंबर 2018 से, कड़े और अनिवार्य प्रमाणीकरण की शर्तों के साथ भारत ने अमेरिका को अपने डेयरी उत्पाद के निर्यात की स्वीकृति दे दी है। इस शर्त के अनुसार अमेरिका के डेयरी उत्पाद का संबंध किसी भी ऐसे पशु से नहीं होना चाहिए जिनके आहार में ''रक्त, आतंरिक अंग, या जुगाली करनेवाले पशु के अधिशेष'' शामिल हो, क्योंकि ये हमारी अधिकांश जनसंख्या के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर अस्वीकार्य है।[13] पश्चिम में, और विशेष रूप से अमेरिका में, लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए दूध देने वाले शाकाहारी पशुओं को रक्त आधारित आहार देना बड़े–बड़े औद्योगिक डेयरी फार्म में एक आम बात है। अभी तक अमेरिका इन शर्तों को मानने में आनाकानी कर रहा है। वह इन्हें ''वैज्ञानिक रूप से अनुचित'' ठहरा रहा है। समाचार में छपी रिर्पोटों से पता चला कि भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से अमेरिका की डेयरी को 5 प्रतिशत प्रशुल्क और सीमित कोटा के आधार पर आंशिक प्रवेश देने के बारे में सोच रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा – क्योंकि भारत में डेयरी प्रदाथों पर मौजूदा प्रशुल्क 30 से 60 प्रतिशत ही है।[14]

अमेरिकी डेयरी उत्पादों को लेकर एक बड़ी चिंता इस बात की भी है कि वे गायों में दूध के उत्पादन को 10–15 प्रतिशत बढ़ाने के लिए 'आनुवंशिक रूप से संशोधित' (जेनेटिकली मॉडिफाइड) एक हार्मोन देते हैं – जिसका नाम 'रेकॉम्बीनैंट सोमाटोट्रोपिन' (Recombinant Somatotropin – rBST) है। इन हार्मोन वाली गायों के दूध का इस्तेमाल आइसक्रीम, मक्खन, चीज़ (cheese), और दही बनाने के लिए किया जाता है। 'अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन' (US Food and Drugs Administration) ने इस हार्मोन के इस्तेमाल को 1993 में ही स्वीकृति दे दी थी। इसका इस्तेमाल अमेरिकी डेयरी उद्योग में काफी व्यापक स्तर पर होता है। परंतु, मानव एवं पशु स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे यूरोपीय संघ, कनाडा तथा कई अन्य देशों में प्रतिबंधित किया गया है। इन सब के बावजूद भी, USMCA समझौते के तहत कनाडा को अमेरिका से हार्मोन वाला दूध के निर्यात के लिए मजबूर किया जा रहा है।[15]

भारत में करीब 15 करोड़ डेयरी किसान हैं, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा दूध का उत्पादन करते हैं। इनमें से अधिकांश किसान छोटे हैं जिनके पास दो या तीन गायें या भैंसें हैं। इसलिए, डेयरी क्षेत्र को ग्रामीण भारत की रीड की हड्डी कहा जाता है। जो भी उत्पादन होता है वह या तो उत्पादकों द्वारा खुद ही इस्तेमाल किया जाता है, या ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–उत्पादकों को बेचा जाता है, या फिर शहरी घरों में सहकारी समितियों तथा छोटे विक्रेताओं के विशाल नेटवर्क की मदद से बेचा जाता है। उपभोक्ता द्वारा किए गए भुगतान का करीब 70 प्रतिशत

---

[13] रक्त आहार (Blood meal) – यह रक्त तथा मारे गए जानवरों के अधिशेष और अपशिष्ट उत्पादों से बना एक उच्च–प्रोटीन पूरक पशु आहार है। निजी कंपनियों का दावा है कि ये पोषण का सस्ता और कारगर स्त्रोत है, जो अमेरिकी डेयरी फार्म और पशु कारखानों में गायों की अमीनो एसिड आवश्यकताओं को पूरा करता है। पर वास्तविकता में, इसका प्रमुख कारण मुनाफा को बढ़ाना है। क्योंकि इस आहार में मारे हुए जानवरों के कचरों का प्रयोग किया जाता है। यह पशु आहार रोग संचरण का भी एक जरिया है और पूरी तरह से अप्राकृतिक है, क्योंकि एक जानवर को उसी की प्रजाति के दूसरे जानवरों का अधिशेष चारे के रूप में खिलाया जाता है।

[14] Reuters, "India offers US dairy, chicken access in bid for a trade deal with Trump", LiveMint, New Delhi, 14 February 2020, https://www.livemint.com/politics/policy/india-offers-us-dairy-chicken-access-in-bid-for-a-trade-deal-with-trump-11581650603957.html

[15] Hormones, cows and the new trade deal: What you need to know, CBC News, 3 Oct. 2018, https://www.cbc.ca/news/canada/usmca-milk-hormones-1.4849423

उत्पादकों को मिल जाता है।[16] अमेरिका में इसका बिलकुल उलटा है। वहां का डेयरी उद्योग कुछेक बड़ी कंपनियों के हाथों में हैं। डेयरी फॉर्म की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, परंतु प्रत्येक फॉर्म में गायों की औसत संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका में करीब 35 प्रतिशत दूध उन डेयरी फॉर्म से आता है जहां 2,500 से भी अधिक गायें हैं, और 45 प्रतिशत उन डेयरी फॉर्म से आता है जहां 1,000 से कम गायें हैं। कुछ बड़ी डेयरी फार्म के पास तो 30,000 से भी ज्यादा गायें हैं। डेयरी क्षेत्र में कीमतें उत्पादन खर्च से भी कम हैं, जिसकी वजह से इन्हें सरकार से भारी सब्सिडी की आवश्यकता पड़ती है। वर्ष 2015 में, अमेरिकी सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में डेयरी क्षेत्र को 2,220 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 1.66 लाख करोड़ रुपये) दिए।[17] इतनी बड़ी सब्सिडी के बावजूद भी अमेरिका में डेयरी क्षेत्र नुकसान में चल रहा है। यहां उत्पादन खर्च बाजार की कमाई से ज्यादा है।[18] निर्माता और प्रसंस्करणकर्ता – विशेष रूप से, क्राफ्ट फूड्स, डीन फूड्स और लैंड ओ'लेकस् (जिनका मालिक 'डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका' नामक एक विशाल सहकारी है) – लागत से कम कीमतों पर दूध खरीदते हैं, जो उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है।

अमरीकी डेयरी उद्योग, चीन के साथ व्यापार समझौते के तहत प्रशुल्क एवं गैर–प्रशुल्क अवरोधों के हटने के बाद, अगले एक दशक में, करीब 2,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 1,72,500 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त कमाई की उम्मीद कर रहा है।[19] इसी तरह, USMCA ने कनाडा के सुरक्षित डेयरी क्षेत्र में अमेरिका के लिए नए बाजार के अवसर खोल दिए हैं।[20] इनमें 'भौगोलिक चिन्ह' (Geographical Indications) जैसे प्रावधान भी शामिल हैं, जिसकी मदद से चीज़ (Cheese) को 'ब्लू' या 'स्विस' जैसे साधारण नाम से भी बेचा जा सकेगा और इस तरह अमेरिकी बाजार प्रवेश से जुड़े भविष्य के नुकसानों को भी रोका जा सकेगा।[21] 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार कमीशन' के अनुसार, USMCA के तहत अमरीकी डेयरी निर्यात में प्रत्येक वर्ष 31.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 2,355 करोड़ रुपये) की दर से वृद्धि होगी।[22] अमेरिका और जापान के बीच मुक्त व्यापार समझौते की कहानी भी ज्यादा अलग नहीं है। अगले 15 सालों में, जापान चीज़ (cheese) के ऊपर लगे प्रशुल्क को 40 प्रतिशत कम कर देगा और व्हेय (whey) प्रशुल्क को 5 से 20 वर्षों में कम कर देगा।[23] दरअसल, 1 जनवरी 2020 को जापान ने सख्त चीज़ (hard cheese) के ऊपर प्रशुल्क को 29.8 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया। और 1 अप्रैल 2020 को इसे और घटाकर 24.2 प्रतिशत कर दिया गया।[24] हाल के व्यापार समझौतों में देखा जा सकता है कि अमेरिका डेयरी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के ऊपर काफी जोर दे रहा है। इससे आसानी से अंदाजा लागाया जा सकता है कि हमारे मामले में भी अमेरिकी कंपनियां भारतीय डेयरी बाजार में भी पर्याप्त हिस्सेदारी चाहेंगी।

---

[16] "An overview of bovine breeding sector in India", Cattle Division, Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India, http://dahd.nic.in/about-us/divisions/cattle-and-dairy-development

[17] Grey, Clark, Shih and Associates Ltd, "American dairy farmers depend on government subsidies", PR Newswire, 8 February 2018, https://markets.businessinsider.com/news/stocks/american-dairy-farmers-depend-on-government-subsidies-1015126442

[18] Grey, Clark, Shih and Associates Ltd, "American dairy farmers depend on government subsidies", PR Newswire, 8 February 2018, https://markets.businessinsider.com/news/stocks/american-dairy-farmers-depend-on-government-subsidies-1015126442

[19] "Trade" International Dairy Food Association, https://www.idfa.org/trade

[20] "Trade" International Dairy Food Association, https://www.idfa.org/trade

[21] "US-Mexico-Canada trade agreement: Likely impact on the US economy and on specific industry sectors", USITC, April 2019, https://www.usitc.gov/publications/332/pub4889.pdf

[22] Mark O'Keefe, "Why USMCA is a big win for US dairy", US Dairy Export Council, 17 January 2020, https://blog.usdec.org/usdairyexporter/usmca-provides-a-win-for-the-us-dairy-industry-and-a-boost-for-us-dairy-exports-0

[23] "Trade" International Dairy Food Association, https://www.idfa.org/trade

[24] "Exports of US dairy products to Japan already increasing", RED TV, 14 January 2020, https://www.rfdtv.com/story/41562402/exports-of-us-dairy-products-to-japan-already-increasing

मुर्गी पालन

पिछले दो दशकों से अमेरिका भारत के मुर्गी बाजार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, जहां वह अपने यहां काल्ड सटोरेजों में रखी और बर्फ में जमी मुर्गी की टांगों को बेच सके। अभी तक वह कामयाब नहीं हो पाया है। भारत ने मुर्गी उत्पाद के ऊपर 100 प्रतिशत प्रशुल्क (tariff or import duty) लगा रखा है। विश्व व्यापार संगठन के अंदर अमरीका के साथ इस मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा है कि भारत ने अमेरिकी मुर्गी एवं अंडे के आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दूसरी तरफ भारत इसे 'एवियन इन्फ्लूएंजा' (avian influenza) के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम के रूप में देखता है।[25]

जैसे ही अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता के पहले चरण पर हस्ताक्षर होगा, यह स्थिति बिलकुल बदल जाएगी। भारत ने आंशिक रूप से अपने बाजार खोलने की और 25 प्रतिशत आयात प्रशुल्क पर अमेरिकी मुर्गी की टांगों के आयात की पेशकश की है। हालांकि, अमेरिकी वार्ताकार इस प्रशुल्क को कम करके इसे 10 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं।[26] भारतीय मुर्गी उद्योग अमेरिका के साथ इस प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते का कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सस्ते मुर्गी के आयात से लाखों घरेलू मुर्गी पालन इकाईयां बंद हो जाएंगी, जिससे करीब 40 लाख लोगों का रोजगार छिन जाएगा। ''अमेरिका में मुर्गी की कीमत इतनी कम है कि मजाक लगता है,'' यह कहना है, के. जी. आनंद का जो 'वेंकटेश्वर हैचेरीज़' के प्रमुख प्रबंधक हैं। वेंकटेश्वर हैचेरीज भारत का अग्रणी मुर्गी मांस उत्पादक है। उन्होंने आगे कहा – ''भारत सरकार किसी एक देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के लाखों किसानों को मौत के घाट नहीं उतार सकती।''[27]

अमेरिका से बर्फ में जमे मुर्गी के आयात का असर केवल मुर्गी किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं के ऊपर ही नहीं पड़ेगा बल्कि मक्का और सोयाबीन उगाने वाले भारत के लाखों छोटे और सीमांत किसानों के ऊपर भी पड़ेगा। मक्का और सोयाबीन, दो ऐसी प्रमुख फसलें हैं, जिनसे मुर्गियों का आहार बनता है। भारत इनके उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अमेरिका में, मुर्गियों को जो मक्का और सोयाबीन खिलाया जाता है, वह आनुवंशिक रूप से संशोधित (जेनेटिकली मॉडिफाइड) होता है।[28] आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों (GMO crops) में भारत में अभीतक केवल बी. टी. कपास को अनुमति मिली है। डेयरी पशुओं के आहार की ही तरह, अमेरिकी मुर्गी के आहार में भी मांस होता है, जो प्रमुख रूप से गाय और सूअर के मांस से बना होता है। यह जटिलता यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका में मुर्गी को मारने के बाद उन्हें क्लोरीन (chlorine) से धोया जाता है, ताकि उनमें मौजूद सालमोनेला (salmonella) बैक्टीरिया नष्ट हो जाए।

गाय और सूअर के मांस का अंश, अनुवांशिक रूप से संशोधित (जेनेटिकली मॉडिफाइड) आहार, एवं क्लोरीन की धुलाई – अमेरिकी मुर्गी के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त हैं। पर फिर भी हो सकता है कि अमेरिका–भारत मुक्त व्यापार समझौते में इस पर प्रतिबंध लगाए रखना संभव न हो पाए। अगर हम जनवरी 2020 में हुए अमेरिका और चीन के समझौते को देखें तो यह पता चलता है कि समझौते का एक बड़ा हिस्सा चीन द्वारा उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

---

[25] See the latest on this from Amiti Sen, "For 11th time, WTO defers decision on India-US row over poultry ruling implementation", Hindu Business Line, 30 April 2020, https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/for-11th-time-wto-defers-decision-on-india-us-row-over-poultry-ruling-implementation/article31473941.ece

[26] Reuters, "India offers US dairy, chicken access in bid for a trade deal with Trump", LiveMint, New Delhi, 14 February 2020, https://www.livemint.com/politics/policy/india-offers-us-dairy-chicken-access-in-bid-for-a-trade-deal-with-trump-11581650603957.html

[27] Dilip Kumar Jha, "India's RCEP deal with US: Domestic poultry farmers smell death knell", Business Standard, Mumbai, 29 October 2019, https://smartinvestor.business-standard.com/market/Marketnews-606987-storydet-Indias_RCEP_deal_with_US_Domestic_poultry_farmers_smell_death_knell.htm#.Xb7pjZMza9Z

[28] "No harm in feeding livestock GMO feed, new study finds", National Chicken Council, 8 October 2014, https://www.nationalchickencouncil.org/harm-feeding-livestock-gmo-feed-new-study-review-finds/

मानकों को कम करने की प्रतिबद्धता के ऊपर है। उदाहरण के लिए, ग्रोथ हार्मोन के प्रति चीन की ''शून्य सहिष्णुता'' की नीति थी, पर अमेरिका से गौमांस के निर्यात को मंजूरी देने के लिए चीन को अपनी नीति बदलनी पड़ी।[29] बीजिंग उन तमाम लाइसेंस, निरीक्षण और पंजीकरण से जुड़े नियमों को भी आसान बना रहा है जो अमेरिका को व्यापार में अवरोध के रूप में देखे जा रहे हैं।[30] अमेरिकी मुर्गी बाजार में आने के कारण अभी से एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों के ऊपर गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। वियतनाम में, 'एनिमल हसबेंडरी एसोसिएशन' को 2012 में एक शिकायत दर्ज करना पड़ा था क्योंकि अमेरिका की सब्सिडी वाली मुर्गियों को स्थानीय बाजार में कम कीमतों पर बेचा जा रहा था।[31] दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका से लागत से कम कीमत पर मुर्गी आयात के कारण करीब एक तिहाई कामगारों का रोजगार खत्म हो गया, क्योंकि उससे अनेकों मुर्गी फार्म का व्यापार तबाह हो गया।[32]

अमेरिका के मुर्गी व्यापार के ऊपर 5 बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा है – टाइसन फूड्स, पिलग्रिम्स प्राइड, सैंडर्सन फार्म्स, परड्यू फार्म्स, और कोच फूड्स। 2016 में इनका नियंत्रण करीब 50 प्रतिशत मुर्गी, गाय और सूअर के बाजार के ऊपर था। मुर्गी पालन करने वाले सभी किसान ठेकेदारों के ऊपर इन्होंने अपना शिकंजा कसा हुआ था। ब्राज़ील के बाद अमेरिका ही दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी निर्यात करने वाला देश है। ये दोनों देश मिलकर दुनिया भर में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा मुर्गी मांस का निर्यात करते हैं।[33] इसीलिए, अमेरिका के सब्सिडी युक्त मुर्गी आयात के जिस खतरे की बात हम यहॉ कर रहे हैं वो बेबुनियाद नहीं है।

सोयाबीन

सोयाबीन और उसके उत्पाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यापार होने वाले कृषि उत्पाद हैं। कुल वैश्विक कृषि व्यापार में इनका हिस्सा 10 प्रतिशत से भी ज्यादा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है, जो इसके 3 प्रकार के उत्पादों का निर्यात करता है – (i) साबुत सोयाबीन, (ii) सोयाबीन आहार, और (iii) सोयाबीन का तेल। वर्ष 2000 के बाद से एशिया और यूरोप में मांस और मुर्गी की मांग बढ़ने के कारण अमेरिकी सोयाबीन का निर्यात नाटकीय रूप से बढ़ गया। 2017 तक, चीन इसका सबसे बड़ा आयातक रहा। परंतु वाशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यापार विवाद बढ़ने के कारण अमेरिकी सोयाबीन की कीमत तेजी से गिर गई और चीन अमेरिका के बदले ब्राजील और रूस से माल खरीदने लगा। परंतु जब जनवरी 2020 में अमेरिका और चीन ने अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रथम चरण के ऊपर हस्ताक्षर किए, तो सोयाबीन और सोयाबीन तेल को उसमें शामिल किया गया। चीन से अपेक्षा की जा रही है कि 2020–2021 के बीच, 2 वर्ष की अवधि में वह 3,200 करोड़ डॉलर (करीब 2,32,500 करोड़ रुपये) मूल्य के अमेरिकी कृषि सामान का अतिरिक्त आयात करेगा। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका के सोयाबीन निर्यात के ऊपर पानी फिर गया।[34]

---

[29] Reuters, "China proposes standards on hormone residues in beef after US trade deal", 12 Mar 2020, https://www.bilaterals.org/?china-proposes-standards-on

[30] Peter Eavis et al, "What's in (and not in) the US-China trade deal", New York Times, 15 January 2020, https://www.nytimes.com/2020/01/15/business/economy/china-trade-deal-text.html?auth=link-dismiss-google1tap

[31] "Alleged dumping of US chicken legs hurts Vietnam's businesses, association say", eFeedLink, 30 July 2015, http://m.efeedlink.com/contents/07-30-2015/3e93e528-3dac-4fd7-b638-0bbf2b625fb8-a181.html

[32] Friday Phiri, "US 'dumping' dark meat chicken on African markets", IPS, 6 July 2017, http://www.ipsnews.net/2017/07/u-s-dumping-dark-meat-chicken-african-markets/

[33] Daniel Workman, "Chicken exports by country, world top exports", 1 April 2020, http://www.worldstopexports.com/chicken-exports-by-country/

[34] Year on year exports of US soybeans to China were down 40% in the first quarter of 2020. Yen Nee Lee, "China's purchases of US goods will fall way short of 'phase one' trade deal due to coronavirus, says think tank", CNBC, 11 May 2020, https://www.cnbc.com/2020/05/11/coronavirus-us-exports-to-china-to-fall-short-of-phase-one-trade-deal-says-csis.html

भारत कभी भी अमेरिकी सोयाबीन का महत्वपूर्ण आयातक नहीं रहा है। हां, बीच–बीच में जरूर अमेरिका से थोड़ा बहुत सोयाबीन तेल और (साबूत नहीं बल्कि टुटे) सोयाबीन का आयात करता रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन अनुवांशिक रूप से संशोधित (जेनेटिकली मॉडिफाइड) पद्धति से होता है। भारत अनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन के आयात की अनुमति नहीं देता है। परंतु अब लगता है कि अमेरिका–भारत मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत के बाजार अमेरिकी सोयाबीन और सोयाबीन तेल से भर जाएंगे। इस समझौते के कारण भारत के 'जैव सुरक्षा नियमों' (biosafety regulations) को कमजोर बना दिया जाएगा जिससे भविष्य में सोयाबीन और सोयाबीन आहार के आयात का रास्ता साफ हो जाए।

अमेरिकी अनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन के आयात से न सिर्फ भारत के लाखों सोयाबीन उत्पादक संकट में आ जाएंगे बल्कि सोयाबीन खाने वाले करोड़ों शाकाहारी उपभोक्ताओं के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक है। यहां करीब 90 प्रतिशत सोयाबीन का उत्पादन तेल निकालने और खली बनाने के लिए किया जाता है, जिनका भारी मात्रा में (गैड़ अनुवांशिक पशु आहार) निर्यात किया जाता है। देश के कई इलाकों में सोयाबीन उत्पादन के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत अच्छी हुई है, क्योंकि इसके सह–उत्पादों (by-products) की भी बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है।[35]

लागत से भी कम मूल्य में जब अमेरिका के अत्यधिक सब्सिडी वाले सोयाबीन का आयात होगा तो भारत में कीमतें गिर जाएंगी। इससे भारतीय सोयाबीन उत्पादकों का रोजगार नष्ट हो जाएगा। अमेरिका की 'कृषि एवं व्यापार नीति संस्थान' (IATP) के एक शोध से पता चलता है कि अमेरिका में सोयाबीन को दिये जाने वाला 'उत्पाद समर्थन' (commodity support) सीधे कृषि–व्यापार कॉरपोरेट को जाता है, न कि किसानों को। दरअसल, अमेरिकी किसानों को उनकी फसल के लिए जो कीमत प्राप्त होती है वह आम तौर पर उनकी लागत खर्च से भी कम होता है।[36] अमेरिका–भारत व्यापार समझौते के बाद भारत के बाजार सस्ते अमेरिकी सोयाबीन से भर जाएंगे, जो भारत के लाखों सोयाबीन उत्पादकों को बर्बाद कर देगा।[37]

मक्का

मक्के का भी अमेरिका में निर्यात के लिए जरूरत से ज्यादा उत्पादन किया जाता है। 2018–2019 में अमेरिका में करीब 40 करोड़ मेट्रिक टन मक्के का उत्पादन हुआ था, जिसमें से करीब 14 प्रतिशत का 73 से भी अधिक देशों में निर्यात किया गया था।[38] क्योंकि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी पशुओं का झुंड है, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादक है, और चौथा सबसे बड़ा अंडे का उत्पादक है – भारत अमेरिकी मक्के के लिए एक विशालकाय बाजार बन सकता है। इस वक्त भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित मक्के के ऊपर प्रतिबंध होने के कारण अमेरिका भारत में निर्यात नहीं कर पा रहा है। अमेरिकी कंपनियों की नजर भारत में बढ़ती जैव इंधन की जरूरतों के ऊपर भी है, जो अमेरिकी मक्के के लिए एक और बड़ा अवसर प्रदान कर सकती है। 'अमेरीकी अनाज काउंसिल' (US Grains

---

[35] "Evaluation of the PPPIAD project on soybean", Agriculture Division, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, http://ficci.in/spdocument/20539/SOYBEAN-Report.pdf

[36] Sophia Murphy and Karen Hansen-Kuhn, "Counting the costs of agricultural dumping", IATP, June 2017, https://www.iatp.org/sites/default/files/2017-06/2017_06_26_DumpingPaper.pdf

[37] "India set to plant more land with soybean crops as prices rally", Reuters, 21 May 2019, https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/india-set-to-plant-more-land-with-soybean-crops-as-prices-rally/articleshow/69426028.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

[38] US Grains Council, "Maize - production and exports", https://grains.org/buying-selling/maize/

Council) भारत के विशालकाय बाजार को अमेरिकी निर्यात के लिए खोलने की लगातार कोशिश कर रहा है। हो सकता है अब अमेरिका–भारत मुक्त व्यापार समझौते की मदद से वे ये कर पाने में कामयाब हो जाएं।[39]

चावल और गेहूं के बाद, मक्का भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। मक्के का हिस्सा कुल अनाज उत्पादन का 10 प्रतिशत है। मक्के का इस्तेमाल केवल मानव एवं पशु आहार के रूप में ही नहीं होता है बल्कि हजारों अन्य औद्योगिक उत्पादन में कच्चे माल के रूप में भी होता है।[40] मुर्गी आहार और स्टार्च की बढ़ती मांग के कारण 2019 में भारत में इसका आयात 10 लाख टन तक पहुंच गया।[41] इस वजह से मक्के की स्थानीय कीमतें गिरती जा रही हैं। जैसा कि सोयाबीन के मामले में देखा गया, अमेरिका ने अपने सस्ते मक्के से अंतरराष्ट्रीय बाजार को भर रखा है। अमेरिका अपने मक्के को लागत से 12 प्रतिशत कम खर्च में बेच रहा है।[42] अगर अमेरिका–भारत के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में मक्के को शामिल कर दिया गया और अमेरिका अपने मक्के का इतने कम दाम में भारत को निर्यात करे तो भारतीय मक्के की घरेलू कीमत तेजी से गिर जाएगी। इससे भारी मात्रा में मक्का उत्पादन और रोपण क्षेत्र में कमी आएगी। फलस्वरूप, भारत के मक्का उत्पादकों की स्थिति वैसी हो जाएगी जैसी अमेरिका के साथ नाफ्टा (NAFTA) व्यापार संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद मेक्सिको के मक्का उत्पादकों की हुई थी। नाफ्टा समझौता के बाद मेक्सिको के बाजार को अमेरिका ने अपने सस्ते मक्के से भर दिया था, जिससे करीब 20 लाख से अधिक मैक्सिकन लोगों का रोजगार खत्म हो गया था।[43]

अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता के तहत विनियामक बदलाव

ट्रम्प के व्यापार समझौते, चाहे 'मिनी' हों या कुछ और, केवल प्रशुल्क (tariff / import duty) के बारे में नहीं हैं। वे सामने वाले देश को अपने यहां के विनियामक ढांचे (regulatory frameworks) में बड़े बदलाव लाने के लिए भी मजबूर करते हैं, जब भी उन्हें लगता है कि वे अमेरिकी व्यापार गतिविधियों में रुकावट बन सकते हैं।

USMCA में कृषि और खाद्य उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने के लिए 'स्वास्थ्य, खाद्य संरक्षा और विपणन मानकों के समन्वय (harmonisation) का प्रावधान है।[44] अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता के तहत 'समानीकरण' का मतलब है – अमेरिका में जिन स्वास्थ्य एवं खाद्य संरक्षा (food safety) उपायों का अभाव है, दूसरे देश भी अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लें। अर्थात्, स्वास्थ्य एवं खाद्य संरक्षा आधारित अवरोधों को जितना ज्यादा हो सके कम (या खत्म) किया जाए जिससे व्यापार तेजी से बढ़ सके। USMCA के अंदर विनियमन के मामले में अच्छे आचरण के ऊपर एक पूरा अध्याय है। एक दूसरा अध्याय 'सैनिटरी' मानकों के ऊपर है जो तीनों देशों के स्वास्थ्य और संरक्षा मानकों के बीच 'समतुल्यता' को आगे बढ़ाता है।[45] इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश यह कहता है कि

---

[39] US Grains Council, "India/South Asia", https://grains.org/office/india/

[40] Government of India, "Agricultural Statistics at a Glance 2018", January 2019, http://agricoop.gov.in/sites/default/files/agristatglance2018.pdf

[41] "India expected to import up to 1 mt of maize in 2019", Reuters, 28 February 2019, https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/india-expected-to-import-up-to-1-mt-of-maize-in-2019/article26394897.ece

[42] The figure is for 2015. Sophia Murphy and Karen Hansen-Kuhn, "Counting the costs of agricultural dumping", IATP, June 2017, https://www.iatp.org/sites/default/files/2017-06/2017_06_26_DumpingPaper.pdf

[43] "More information on the North American Free Trade Agreement (NAFTA)", https://www.citizen.org/article/more-information-on-the-north-american-free-trade-agreement-nafta/

[44] Sharon Anglin Treat, "FAQ–regulatory cooperation, harmonization and 'good regulatory practices' in USMCA", IATP, 16 January 2019, https://www.iatp.org/new-nafta-grp

[45] USMCA, Chapter 28, https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/28_Good_Regulatory_Practices.pdf

कोई उत्पाद उनके नियमों के अनुसार सुरक्षित है तो दूसरे देशों को भी उस उत्पाद को सुरक्षित के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा (चोहे वह उत्पाद वहां असुरक्षित ही क्यों ना धोशीत हो)। इसके साथ–साथ इसका मकसद यह भी है कि इन मामलों में निर्धारण प्रक्रिया की गति बढ़ाई जाए। हालांकि, कहने के लिए तो देशों को अधिकार दिए गए हैं कि वे 'सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों' के आधार पर अपने मानक तय कर सकते हैं और इस पर बातचीत कर सकते है, परंतु वास्तविकता में ये कैसे होगा यह देखा जाना अभी बाकी है। अमेरिकी बीज उद्योग इस बात से काफी उत्साहित है कि USMCA समझौता ''नए पौध प्रजनन के महत्व को कैसे देखेगा, जिसमें जीन एडिटिंग जैसे नए तरीके भी शामिल हैं, और जिसमें कृषि जैव–प्रौद्योगिकी (biotechnology) के व्यापार से संबंधित सूचना विनिमय (information exchange) और सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं।''[46]

इसी प्रकार, अमेरिका–चीन व्यापार समझौते के अंतर्गत चीन को अमेरिका से आयातीत उत्पादों को तेजी से खाद्य संरक्षा निरीक्षण स्वीकृति और अनुवांशिक रूप से संशोधित उत्पादों को स्वीकृति देने जैसे प्रावधान थोपे गए हैं।[47] इस समझौते के फलस्वरूप, दिसंबर 2019 में चीन ने अमेरिका से अनुवांशिक रूप से संशोधित पपीता और सोयाबीन के आयात को स्वीकृति देनी पड़ी। और उसके एक महीने बाद, पशु आहार के लिए पांच अन्य अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को भी स्वीकृति दे दी गई।[48]

अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम (यू.के. या ग्रेट ब्रिटेन) के बीच मौजूदा व्यापार वार्ता में अमेरिकी कृषि–व्यवसाय गुट (agribusiness lobby) यूनाइटेड किंगडम के ऊपर उनके कीटनाशक, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों, और मुर्गी और मांस उत्पादन से संबंधित विनियामक मानकों (regulatory standards) को खत्म करने का दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी, कारगिल (Cargill) ने यह मांग की है के अमेरिका अपनी कंपनियों के लिए यूनाइटेड किंगडम से ''कृषि बाजार तक संपूर्ण पहुंच'' की मांग करे और ''कृषि क्षेत्र में सभी अपेक्षित और अनपेक्षित गैर–प्रशुल्क (non-tariff) अवरोधों को हटाय जाने पर दबाव बनाए''।[49] इसका यूनाइटेड किंगडम की खाद्य संरक्षा के ऊपर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता हैं। इससे यूनाइटेड किंगडम को मजबूरन अपनी सीमाओं को हार्मोन वाली गायों, क्लोरीन से धुली मुर्गियों के मांस और अनुवांशिक रूप से संशोधित आहार के लिए खोलना होगा, जो अभी तक यूनाइटेड किंगडम में प्रतिबंधित है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम को अमेरिका से आयातीत उन कीटनाशकों की मदद से उगाए गए फल और सब्जियां को भी बेचने की अनुमति देनी होगी जो पर्यावरणीय और संरक्षा के आधार पर यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ में पुरी तरह प्रतिबंधित हैं। 'अमेरिकी चीनी गठबंधन' (American Sugar Alliance) भी यू.के. के उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद 'फूड लेबलिंग' के ऊपर सवाल उठा रहा है, जिसे वार्ताकारों द्वारा ''गैर–प्रशुल्क व्यापार अवरोध'' के रूप में पेश किया जा रहा है।[50] इन मांगों ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच पुरानी व्यापार बातचीत में जहर घोल दिया था, जो ट्रम्प के राष्ट्रपति चुने जाने के समय पूरी तरह से रुक गई थी। परंतु अब ट्रम्प के दौर में मिनी स्तर पर ये बातचीत फिर से शुरू हो रही है।

---

[46] Treena Hein, "USMCA and IP protection", Seed World, 17 April 2020, https://seedworld.com/usmca-and-ip-protection/

[47] Ana Swanson and Keith Bradsher, "What's really in the trade deal trump announced with China", New York Times, 15 October 2019, https://www.nytimes.com/2019/10/15/business/economy/china-trade-deal.html

[48] Anubhuti Vishnoi, "GM trade war back on front burner as Trump comes to India", The Economic Times, 29 January 2020, https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/gm-trade-war-back-on-front-burner-as-trump-comes-to-india/articleshow/73717804.cms

[49] Laurence Carter and Zach Boren, "US agribusiness lobby calls on Trump to target UK food and environment rules in Brexit trade deal", Unearthed, 18 January 2019, https://unearthed.greenpeace.org/2019/01/18/us-agribusiness-lobby-calls-on-trump-to-target-uk-food-and-environment-rules-in-brexit-trade-deal/

[50] Lawrence Carter and Zach Boren, "US agribusiness lobby calls on Trump to target UK food and environment rules in Brexit trade deal", Unearthed, 18 January 2019, https://unearthed.greenpeace.org/2019/01/18/us-agribusiness-lobby-calls-on-trump-to-target-uk-food-and-environment-rules-in-brexit-trade-deal/

इस मोर्चे पर भारत को भी जोरदार लड़ाई लड़नी होगी – अगर समझौते की बातचीत आगे बढ़ती है। 2018 में 'अमेरिका–भारत व्यापार काउंसिल' ने यह सिफारिश दी थी कि अगर किसी भी उत्पाद में 5 प्रतिशत से ज्यादा अनुवांशिक रूप से संशोधित सामग्री हो तो उसे भारत में बेचने के लिए उपयुक्त रूप से लेबल लगाना होगा। ये भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन की शुरुआत करने की एक चाल है, जो इस वक्त प्रतिबंधित है।[51] इसी तरह से, अमेरिकी कंपनियां पिछले कई सालों से भारत को अनुवांशिक रूप से संशोधित पशु आहार आयात करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही हैं। हाल ही में, भारत की 'जिनेटिकली मॉडिफाइड विनियमन इकाई' (GM regulatory body) ने इसे संभवतः अनुमति देने के लिए और अधिक जानकारियां मांगी हैं। इस प्रकार भारत में व्यापार प्रतिबंधों को ढीला करने के लिए अमेरिकी कॉर्पोरेट का दबाव लगातार बढता जा रहा है।

USMCA हो या अमेरिका–चीन मुक्त व्यापार समझौता – दोनों में ही आयातित भोजन और कृषि उत्पादों में अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव का ''निम्न स्तर की उपस्थिति'' की स्वीकार्यता का प्रावधान है। USMCA समझौते के अनुसार, मेक्सिको जैसे आयात करने वाले देशों को सुनिश्चित करना है कि अमेरिका से आयातीत भोजन और कृषि उत्पादों में ''अनजाने में'' अनुवांशिक रूप से संशोधित सामग्री की मौजूदगी को तेजी से निपटाया जाए और उस वक्त ये ध्यान रखा जाए की इस अनुवांशिक उत्पाद के लिए संरक्षा मंजूरी निर्यातकों को ही देनी है।[52] दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निम्न स्तर पर मौजूद अनुवांशिक रूप से संशोधित सामग्रियों को मंजूरी देनी ही है – राष्ट्रीय कानूनों की परवाह किए बिना। अमेरिकी और चीन मुक्त व्यापार समझौते के प्रथम चरण में भी यह प्रावधान है। चीन को अमेरिका या अन्य देशों के जी.एम.ओ. के सुरक्षा आकलन (safety assessments) को ध्यान में रखना और मानना होगा, जिन्हें चीन में ''अनजाने में'' निर्यात किया जा रहा है।[53]

अभी तक जैव–प्रौद्योगिकी से बने किसी भी खाद्य फसल को भारत में उपभोग की मंजूरी नहीं दी गई है। ''निम्न स्तर की उपस्थिति'' का प्रावधान भारतीय खाद्य व्यवस्था में उन अनुवांशिक रूप से संशोधित सामग्रियों की मिलावट को वैधानिक बना देगा जिन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा मानव उपभोग के लिए स्वीकृत नहीं किया गया है।

USMCA और अमेरिका–चीन समझौता, दोनों में कृषि जैव–प्रौद्योगिकी के ऊपर अलग से खंड है, जिसमें अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने की बाध्यता है। दरअसल, USMCA की परिभाषा के अंदर 'जीन संपादन' (gene editing) के नए तरीके भी शामिल हैं।[54] यह पारदर्शिता, विनियामक स्वीकृति वाले उत्पादों की समय रहते समीक्षा, और उनके बीच सहयोग को रेखांकित करता है। अमेरिका–चीन समझौते के अंदर – कृषि जैव–प्रौद्योगिकी के उत्पादों के लिए स्वीकृति प्रक्रिया का तेजी से निपटान, किसी भी आवेदन को चालू अवस्था में या साल भर के आधार पर निपटान, और इन प्रक्रियाओं के लिए 24 महीनों की समय सीमा – जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। एक बार स्वीकृति मिल जाए तो प्राधिकरण अवधि (authorisation period) कम से कम 5 साल की होगी।[55] इस तरह के प्रावधानों का भारत के ऊपर भयानक प्रभाव होगा, जहां अभी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित सामग्रियों (जैसे बिज, पौद्य) की मंजूरी प्रक्रिया में पर्यावरण सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दों को बहुत महत्व दिया जाता है।

---

[51] Rhythma Kaul, "FSSAI considering 1% as labelling requirement for genetically modified food items", Hindustan Times, 20 December 2018, https://www.hindustantimes.com/india-news/fssai-considering-1-as-labelling-requirement-for-genetically-modified-food-items/story-7AQSuDGj8Faf2OFrqZsgjJ.html

[52] USMCA, Chapter 3, https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/03_Agriculture.pdf

[53] Jim Wiesemeyer, "U.S./China Phase 1 Accord: What You Need to Know", ProFarmer, 16 January 2020, https://www.profarmer.com/index.php/markets/policy/us/china-phase-1-accord-what-you-need-know. See USMCA, Chapter 3, op cit.

[54] "Agricultural provisions of the US-Mexico-Canada agreement", Congressional Research Service, 8 April 2019, https://fas.org/sgp/crs/row/R45661.pdf

[55] Peter Lunenborg, "US-China trade deal: preliminary analysis of the text from WTO perspective", South Centre, February 2020, https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/02/PB72_US-China-trade-deal-preliminary-analysis-of-the-text-from-WTO-perspective_EN-1.pdf

यू.पी.ओ.वी. (UPOV) के माध्यम से बीजों पर एकाधिकार

ट्रम्प के व्यापार समझौतों में एक और बड़ी समस्या ये है कि इनमें सहभागी देशों को ''यूपोव (UPOV 1991) अर्थात् 'पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय यूनियन'' के 1991 की संधी में शामिल होना अनिर्वय है जिसके अंतर्गत बीजों के ऊपर पेटेंट का अधिकार दिया जाता हैं। यूपोव 1991 को थोपने का संबंध केवल ट्रम्प प्रशासन से ही नहीं है, बल्कि 1990 के दशक के बाद हुए सभी अमेरिकी व्यापार समझौतों का यह मूल पहलू रहा है। मेक्सिको पहले से ही यूपोव 1978 का सदस्य है, पर USMCA के तहत अब मेक्सिको के ऊपर पहले से भी ज्यादा कठोर यूपोव 1991 को स्वीकार करने की बाध्यता है। अमेरिकी बीज उद्योग इससे बहुत उत्साहित है, वे इसे अपनी ''जीत'' मानते हैं।[56]

अमेरिका–चीन समझौते के पहले चरण में यूपोव 1991 का कोई जिक्र नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं – अमेरिका इस समझौते के दूसरे चरण में व्यापक बौद्धिक संपदा अधिकार (intellectual property rights) के मुद्दे को उठाना चाहता हो; या चीन, जो मेक्सिको की तरह, पहले से ही यूपोव 1978 का सदस्य है, हो सकता है कि वह खुद ही धीरे–धीरे अपने बीज कानूनों को यूपोव 1991 के अनुरूप ढाल रहा हो।[57]

भारत की नीति, अभी तक, यूपोव में शामिल नहीं होने की रही है, जिससे वह लाखों छोटे किसानों और गैर–कॉर्पोरेट पौध प्रजनकों के हितों को सुरक्षित रख सके। प्रस्तावित अमेरिका–भारत मुक्त व्यापार समझौते में अगर भारत सरकार के ऊपर यूपोव में शामिल होने का दबाव डाला गया तो हमारे किसानों के अधिकारों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में भारतीय किसानों के साथ 2019 में जो कांड हुआ था, जिसमें कथित तौर पर पेप्सिको कंपनी ने अपनी आलू के एक किस्म के बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन का आरोप गुजरात के कुछ किसानों पर लगाया गया था। यह पूरी तरह से संभव है कि अमेरिकी बीज उद्योग इस समझौते के माध्यम से भारत में एक मजबूत बीज एकाधिकार की बात करेंगे और किसानों द्वारा बीज बचाने की संभावनाओं को खत्म करना चाहेंगे।

निष्कर्ष

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार आर.सी.ई.पी. व्यापार वार्ताओं से इसलिए बाहर निकल आई क्योंकि उसमें भारत के डेयरी उत्पादक, किसानों और अन्य उद्योग क्षेत्रों की संवेदनशीलता को संबोधित नहीं किया जा रहा था।[58] आर.सी.ई.पी से बाहर आने के बाद अगर अब फिर से भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता शुरू करता है, जो भारतीय ग्रामीण समुदायों और कृषि क्षेत्र के लिए पहले से कहीं बड़ी चुनौती लेकर आया है, तो यह न सिर्फ असंगत होगा, बल्कि *मुंह की खाने* जैसा होगा। इस तरह के समझौते से भारत स्थानीय बीजों और पौधों की विशाल विविधता से हाथ धो बैठेगा, जिन्हें साल दर साल देश के करोड़ों किसान संरक्षित करते आए। यह भारत की खाद्य संप्रभुता की आशा को भी खत्म कर देगा। अब समय आ गया है कि भारतीय किसान फिर से उठें और अमेरिका–भारत व्यापार समझौते को औपचारिक रूप देने के किसी भी (अभी की या भविष्य की) संभावना का विरोध करें।

***

[56] American Seed Trade Association, "Passage of USMCA is a win for the US seed industry", 16 January 2020, https://www.betterseed.org/passage-of-usmca-is-a-win-for-the-u-s-seed-industry/

[57] Liz Freeman Rosenzweig, "Essentially derived varieties and the role of leading cases in Chinese plant variety protection", China IPR, 2 April 2020, https://chinaipr.com/category/upov/?blogsub=confirming#blog_subscription-3

[58] "Conditions diluting Indian interest under RCEP", Rajya Sabha, Parliament of India, Unstarred Questions No 2132, answered by Ministry of Commerce and Industry, Government of India, 6 December 2019, https://pqars.nic.in/annex/250/AU2132.pdf